E-Newsletter
October

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

LSG

Local Self Government
Rajasthan

Minimum Government, Maximum Governance

सत्यमेव जयते

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

Local Self Government Rajasthan

The Department of local self Government, Rajasthan is the controlling Department of all municipalities for all administrative purposes. It also performs monitoring and co-ordination function at the state level for all the 188 municipal bodies of the state.

Functions of Department of Local Self Government Rajasthan

* *Appointment of OICs/Advocate in Court Cases, vetting of reply, opinion on judgment, decision for appeal or no appeal, scrutiny of Bye-Laws and Rules and Amendments in Acts and Rules.*
* *Approval of Budget of ULBs and released of funds regarding Special Grant, General Grant, SFC, TFC, Grant (in Lieu of Octroi) and State/Centrally Sponsored Schemes/Programme.*
* *Disposal of matters related to transfer, establishment, DPCs related to officers and staff of ULBs, DDR offices and Directorate.*
* *Extension and Exclusion of Municipal boundary, Election of Municipal Boards.*
* *Implementation of HRD Plan for elected representatives, and officials of ULBs.*
* *Implementation of Poverty Alleviation and social responsibilities Programmes.*
* *Issuance of Financial, Administrative and Technical Sanctions which are not in the Jurisdiction of the elected board.*
* *Preparation of Annual Plan/District Plan/Action Plan/DPRs related to various GoI/GoR schemes/Programmes.*

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

Various Schemes

AMRUT – (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation)

Urban Infrastructure Development of 29 Towns > 1.0 lac population.

Total Estimated Project cost Rs 4500 cr (50% GoI, 30% GoR, 20% ULB)

Components to be covered - Water supply, Sewerage network, Septage management, Storm water drainage, Urban Transport, Green spaces and parks.

HRIDAY-Heritage Cities Infrastructure Development & Augmentation

- Ajmer – Pushkar nominated under HRIDAY– 100% grant by GoI.
- City HRIDAY Plan for Rs 48.00 cr. approved by MoUD, GoI.

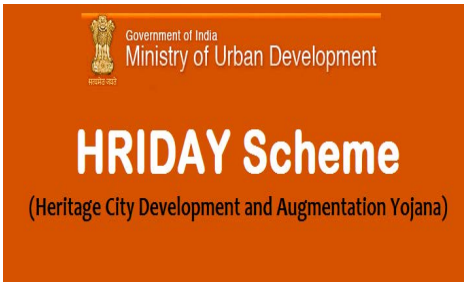

National Urban Livelihood Mission (NULM)

- Focus on Skill Training & Placement and Capacity Building / Self Employment.
- Major components- Shelter for Urban Homeless, Support to Urban Street Vendors.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

स्मार्टराज कॉल सेन्टर

आम जनता की शिकायतों को हल करने का अनूठा प्रयास ....

स्वायत्त शासन विभाग कार्यालय में आमजन के लिए स्मार्ट राज कॉल सेन्टर दिनांक 11.05.2015 माननीय मंत्री महोदय श्री राजपाल सिंह शेखावत द्वारा उद्घाटन कर प्रारंभ किया गया है। जिसके टोल फ्री नंबर 1800–180–6127 है जिसमें आईवीआर नं0 2 तत्पश्चात् 1 पर आमजन की कॉल प्राप्त कर उन्हें विभाग के संबंध में चाही गई जानकारियां उपलब्ध कराये जाने के साथ–साथ नगरीय निकायों व विभाग से संबंधित शिकायतें सम्पर्क पोर्टल पर निरंतर दर्ज की जा रही है। 11 मई 2015 से 30 अप्रैल 2016 तक 109588 कॉल प्राप्त हुई एवं 8600 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें से 5894 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है।

दर्ज शिकायतों को संबंधित निकायों/निदेशालय के अनुभागों को प्रेषित किया जाता है तथा जो शिकायतें अन्य विभागों से संबंधित है, उन्हें संबंधित विभागों में स्थानांतरित किया जाता है। शिकायतों के लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु कॉल सेन्टर के नोडल अधिकारियों को कॉल कर अवगत/निर्देशित किया जाता है तथा उनसे प्राप्त जवाब को भी निरंतर दर्ज कर दैनिक रिपोर्ट बनाई जाती है।

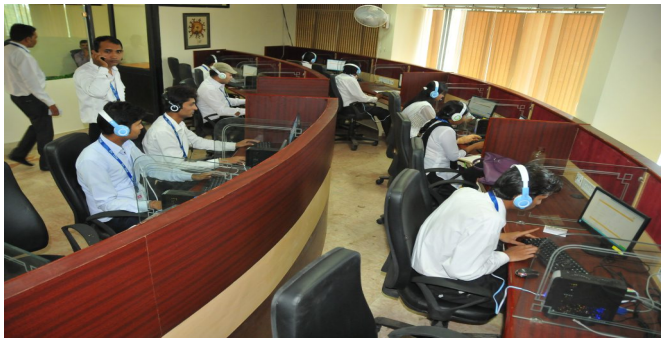

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

स्वच्छ भारत मिशन

खुले में शौच से मुक्त की राह में राजस्थान ....

स्वच्छ भारत मिशन माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा चलाया गया भारत सरकार का अत्यन्त महत्वपूर्ण अभियान है जो 02 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की 145 जन्मदिन के अवसर पर भारत सरकार की ओर से अधिकारिक तौर पर शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य 2019 तक भारत को 'खुला शोच मुक्त भारत' घोषित करना है। स्वच्छ भारत मिशन के सफल क्रियान्वन हेतु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा LSGD, GoR को नोडल विभाग बनाया गया।

भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत (शहरी) के 10 सितम्बर 2014 के दिशा निर्देशों के अनुसार विभाग द्वारा 'स्वच्छ राजस्थान सप्ताह' मनाया गया जो कि 02 अक्टूबर, 2014 को प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर द्वारा स्वच्छता शपथ लिये जाने के साथ सम्पन्न हुआ।

इसी सप्ताह को क्रमशः आगे बढ़ाते हुए ''स्वच्छ राजस्थान अभियान'' चलाया गया जो दिनांक 21 अक्टूबर 2014 को सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। इन अभियानों के दौरान साफ, सफाई, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया और सामुदायिक जागरूकता हेतु प्रभात फेरी, रेली, श्रमदान आदि जैसे कार्य संपादित हुए। तत्पश्चात राज्य की समस्त निकायों द्वारा 08 नवम्बर से 14 नवम्बर तक सफाई अभियान चलाया गया जो बालदिवस पर सम्पन्न हुआ।

स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों की निगरानी हेतु 12 फरवरी 2015 को राज्य स्तर, जिला स्तर व शहरी स्तर पर समितियों का गठन किया गया। राज्य के 187 शहरी निकायों में 9 मार्च से 27 मार्च तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया जिसके अंतर्गत शहरों में नालों की सफाई, रोड़ की सफाई, पार्को की सफाई, रोड़ लाइटों का रखरखाव, स्कूलों व राजकीय कार्यालयों की सफाई, शौचालय विहीन परिवारों की पहचान (सर्वे द्वारा) आदि शामिल थे साथ ही शहरी स्तर पर प्रत्येक निकायों द्वारा सामुदायिक जागरूकता हेतु विभिन्न कार्यक्रम जिनमें वार्ड़ सभाऐं, नुक्कड नाटक, अपील, रेली आदि आयोजित की गई जिससे जन समुदाय को स्वच्छत्ता व सफाई आदि के महत्व का पता चल सके व खुले में शौच का स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभावों का भी ज्ञान दिया गया। अगस्त 2015 को स्वच्छ भारत मिशन की गतिविधियों में सहयोग व सभी नगरीय निकाय से संपर्क स्थापित कर स्वच्छ भारत मिशन कार्य को गति देने हेतु राज्य स्तर पर परियोजना प्रबंध इकाई (PMU) का गठन किया गया है।

राज्य स्तर पर प्रत्येक संभाग की स्वच्छ भारत मिशन पर आमुखीकरण कार्यशालाओं का आयोजन सी.एम.ए.आर. द्वारा कराया गया प्रथम चरण (9 April, 16 April, 28 April & 29 April, 2015) द्वितीय चरण में परियोजना प्रबंध इकाई (PMU) तथा सिटी मैनेजर्स एसोसिएशन राजस्थान व CSC के संदर्भ व्यक्तियों द्वारा (26th October to 04th November, 2015) तकनीकी अधिकारियों और कम्प्यूटर ऑपरेटरर्स को स्वच्छ भारत मिशन पोर्टल के सम्बन्ध में जानकारी दी गई। कार्यशाला में स्वच्छ भारत मिशन के प्रत्येक घटक को विस्तार पूर्वक बताया गया और प्रत्येक शहरी निकाय को लक्ष्य बताये गए तथा 2015–16 के और संपूर्ण मिशन अवधि 2019 के बारे में जानकारी दी।

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

अमृत मिशन योजना

शहरी नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने हेतु अटल प्रयास...

अमृत योजना (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 28 शहरों के ''सिटी लेवल इम्प्रुवमेंट प्लान'' बनाने के लिए दो दिवसीय ''हैण्ड होल्डिंग'' कार्यशाला (10 व 11 अगस्त) का आयोजन स्वायत्त शासन विभाग के सभागार में किया गया।

इस कार्यशाला में स्वायत्त शासन मंत्री श्री राजपाल सिंह शेखावत ने बताया कि अमृत योजना के तहत बनाये जाने वाले ''सिटी लेवल इम्प्रुवमेंट प्लान'' सम्बन्धित शहर के नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप ही बनाया जाये। जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन में पूर्व में रही कमियों को अमृत योजना (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) में नहीं दोहराया जाये। उन्होनें कहा कि शहरों में सीवरेज योजनाओं के प्रारम्भ करने से पूर्व में जारी पेयजल योजनाओं के सशक्तीकरण एवं सेवा स्तर को सुधारते हुए कवरेज (आवृत) क्षेत्र में गेप पूरा किया जाए। उन्होने बताया कि अमृत योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार यूनिवर्सल कवरेज (पेयजल एवं सीवरेज) को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है। इसलिए इन क्षेत्रों के गेप को पूरा होने पश्चात् ही अन्य क्षेत्रों में शहरी परिवहन एवं स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज को प्रारम्भ किया जाये।

स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव, डॉ. मनजीत सिंह ने बताया कि अमृत योजना में शहरी नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारना एक प्रमुख लक्ष्य है। इसके तहत योजना में सम्मिलित प्रत्येक नगरीय निकाय द्वारा वर्ष में एक उद्यान का विकास किया जाना आवश्यक है। उन्होनें बताया कि अमृत योजना के क्रियान्वयन के लिए परियोजना के तहत एक प्रोजेक्ट डवलपमेंट एण्ड मेनेजमेंट कंसलटेन्ट की नियुक्ति की जायेगी जिसका कार्य शहरों का ''सिटी लेवल सर्विस इम्प्रुवमेंट प्लान'' बनाकर तद्नुसार राज्य की वार्षिक योजना तैयार कर अनुमोदन पश्चात् डीपीआर तैयार करना एवं प्राजेक्ट के क्रियान्वयन का सुपरविजन करना शामिल है।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशक श्री दिनेश कुमार के साथ विशेषज्ञों के दल ने ''सिटी लेवल इम्प्रुवमेंट

प्लान'' (पेयजल सीवरेज शहरी परिवहन स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज एवं उद्यानों) के बनाये जाने के लिए प्रस्तुतीकरण दिया गया। कार्यशाला में निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग श्री पुरूषोत्तम बियाणी, मुख्य अभियंता रूफडिको श्री एस.के. गोयल, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता रूफडिको श्री ललित करोल तथा 28 शहरी निकायों के आयुक्त, अधिशाषी अधिकारी एवं अभियन्ता उपस्थित थे। कार्यशाला का आयोजन RUIFDCO तथा CMAR के संयुक्त तत्वाधान में किया गया।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, एल.ई.डी. लाईट प्रोजेक्ट एवं अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत योजना) की समीक्षा

प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग डॉ.मनजीत सिंह की अध्यक्षता में गुरूवार को स्वायत्त शासन भवन में प्रातः 10:00 स्मार्ट सिटी, दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, एल.ई.डी. लाईट प्रोजेक्ट एवं अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत योजना), मुख्यमंत्री जनावास योजना सहित विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की गई।

बैठक में प्रमुख शासन सचिव डॉ. मनजीत सिंह ने स्मार्ट सिटी परियोजना की समीक्षा करते हुए कहा कि जयपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना में किये जाने वाले कार्यो की गति धीमी है। इस पर जयपुर स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सरवन कुमार ने बताया कि स्मार्ट सिटी परियोजना में अब तक 2 परियोजनाओं की निविदाओं में निविदादाताओं को चयन किया जाकर शीघ्र कार्य प्रारम्भ करवाया जा रहा है। जोधपुर नगर निगम के आयुक्त ने बैठक में बताया कि अमृत योजना के तहत सीवरेज एवं ड्रेनेज योजना की डीपीआर तैयार की जा चुकी है तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब तक 4083 लाभार्थियों को प्रथम किश्त जारी की जा चुकी है एवं 30 वार्डो को खुले में शौच मुक्त किया जा चुका है। शहर में 25 सार्वजनिक शौचालयों, सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जाना था। जिसमें से 3 का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 14 निर्माणाधीन है एवं 8 PPP मोड पर बनाये जा रहे है। उन्होनें बताया कि जोधपुर शहर में प्लास्टिक की 3000 मैट्रिक टन थैलियॉ स्वच्छ नगर अभियान के दौरान जब्त की जा चुकी है तथा संस्थाओं के सहयोग से स्वच्छ नगर अभियान में जनसहयोग से कार्य करवाया जा रहा है। उन्होने बताया कि दिपावली से पूर्व शहर में 70 हजार एल.ई.डी. लाईटें लग जायेगीं। मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के तहत किये जाने वाले कार्यो की डीपीआर तैयार की जा चुकी है।

कोटा नगर निगम के आयुक्त श्री शिव प्रसाद मदान नकाते ने बताया कि स्मार्ट परियोजना के तहत कोटा शहर में 69 करोड़ रूपये की लागत का दशहरा मैदान का डॉक्यूमेंट तैयाद किया गया है। शहर में दो साईकिल शेयरिंग स्टेशन प्रारम्भ किये गये है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत शीघ्र ही कोटा में कोटा स्मार्ट कार्ड प्रोजेक्ट प्रारम्भ किया जा रहा है। अमृत योजना के तहत गार्डन/पार्क एवं शुद्ध पेयजल, स्टॉर्म वाटर की डीपीआर तथा सोलर मास्टर प्लान तैयार किया जा चुका है। उन्होनें बताया कि कोटा में अब तक 5 वार्ड खुले में शौच मुक्त किये जा चुके है तथा सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के तहत किये जाने वाले कार्यो की डीपीआर तैयार की जा चुकी है।

बैठक में प्रमुख शासन सचिव डॉ. मनजीत सिंह ने निद्रेश दिये कि सभी नगरीय निकायों में घरेलू शौचालयों के साथ आवश्यकतानुसार सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों का निर्माण तेजी से किया जाये साथ ही बड़े निर्माणाधीन भवनो/कॉम्प्लेक्सों के निर्माण के दौरान वहॉ कार्य करने वाली लेबर के लिये भी भवन निर्माता को अस्थाई/स्थाई शौचालयों को निर्माण भविष्य में करना होगा। अन्यथा उनके विरूद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जायेगी। बीकानेर नगर निगम के आयुक्त ने बैठक में बताया कि उनके यहॉ पेयजल की डीपीआर बनायी जा चुकी है तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय बनाने का कार्य तेजी से जारी है। शहर के 40 वार्डों में डोर–टू–डोर कचरा संग्रहण का कार्य किया जा रहा है। उदयपुर नगर निगम के आयुक्त ने बताया कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 35 मॉड्यूल एवं पेन सिटी सिटी में 15 मॉड्यूल पर कार्य किया जायेगा। अमृत योजना के तहत सीवरेज, पेयजल की डीपीआर बनायी जा रही है तथा कॉमन डक्टिंग का मॉड्यूल बनाया गया है। शहर में बिजल के तारों को अण्डरग्राउण्ड करने के लिए डीपीआर बनायी गई है तथा 11 हैक्टेयर भूमि का चयन किया गया है। जहॉ पर 5 मैगावाट का सोलर प्लान्ट लगाया जायेगा। उन्होनें बताया कि 5 करोड़ रूपये की

लागत से गोर्वधन सागर पर पार्क बनाया जायेगा। मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के तहत किये जाने वाले कार्यो की डीपीआर तैयार की जा चुकी है।

प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि सभी नगरीय निकायों में पदस्थापित सफाई निरिक्षकों को ई–कोर्स करवाया जायेगा। उन्होनें कहा कि अजमेर में स्मार्ट सिटी के तहत रोड़ साईनेज विकसित किये जाये शीघ्र ही अजमेर में सिटी रोड ट्रांसपोर्ट के तहत छोटी सिटी बसें चलायी जायेगी। जिला कलेक्टर अजमेर श्री गौरव गोयल एवं आयुक्त नगर निगम श्री प्रियवृत पाण्ड्या ने बताया कि अजमेर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय बनाने का कार्य किया जा रहा है एवं सीवर कनेक्शन तेजी से किये जा रहे है। अजमेर में 100 प्रतिशत एल.ई.डी. लाईटें लगायी जा चुकी है तथा दिसम्बर माह में अजमेर को खुले में शौच मुक्त कर दिया जायेगा। अमृत योजना के तहत किये जाने वाले सभी कार्य तेजी से जारी है। अजमेर रिलायंस कम्पनी के ओर से शहर में सीसीटीवी लगाये जा रहे है। मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के तहत किये जाने वाले कार्यो की डीपीआर तैयार की जा चुकी है। नगर परिषद अलवर के आयुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के तहत किये जाने वाले कार्यो की डीपीआर तैयार की जा चुकी है तथा शहर के 12 वार्ड खुले में शौच मुक्त किये जा रहे है तथा 5 वार्डो में डोर–टू–डोर कचरा संग्रहण का कार्य शुरू किया गया है तथा अब तक 8000 एलईडी लाईटें लग चुकी है। नगर परिषद भीलवाड़ा के आयुक्त ने बताया कि पेयजल एवं स्टार्म वाटर की डीपीआर तैयार की जा चुकी है तथा आरयूआईडीपी फेज–तृतीय के तहत सीवरेज का कार्य किया जा रहा है। आयुक्त नगर परिषद गंगानगर ने बताया कि 2.50 करोड़ रूपये की लागत से बनाये जाने वाले उद्यान की डीपीआर तैयार की गई है। अब तक शहर में 10500 में से 9750 एलईडी लाईटें लगायी जा चुकी है तथा स्वच्छ नगर अभियान के तहत 95 क्विंटन प्लास्टिक की थैलियां जब्त की गई है।

बैठक में वरिष्ठ नगर नियोजक श्री राजेन्द्र कुमार विजयवर्गीय ने बताया कि भविष्य में किसी भी नगरीय निकाय में ऑफ–लाईन बिल्डिंग प्लान स्वीकृत नहीं किये जायेंगे। सभी नगरीय निकायों में ऑन–लाईन ही बिल्डिंग प्लान स्वीकृत किये जायेंगे। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के बारे में बताया गया कि अब तक 17 परियोजनाएं झालावाड़, राजसमंद, जोबनेर, ब्यावर, सिरोही, दौसा, हिण्डौन, सरवाड़, खेतड़ी, पाली, बून्दी, आबूरोड़, केशवरायपाटन, डूंगरपुर, शिवगंज मे 8424 ईडब्ल्यूएस मकान एवं 5328 लोअर इनकम ग्रुप (एलआईजी) मकान राशि रूपये 648.216 करोड़ स्वीकृत किये गये है।

प्रमुख शासन सचिव ने बैठक में सभी नगरीय निकायों को निर्देश दिये कि निकायों के जिन क्षेत्रों में सीवरेज लाईन नहीं है वहॉ पर सेप्टॉज मैनेजमेंट के तहत सभी शहरों में रेपिड असेसमेंट करवाया जाये एवं यह देखा जाये कि शहर में कहॉ–कहॉ सीवर लाईनें है एवं कहॉ–कहॉ पर सेप्टी टैंक है। उन्होंने कहा कि सभी नगरीय निकायों को सेप्टॉज मैनेजमेंट के दिशा–निर्देश भिजवाये जा चुके है। उन्होनें दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की समीक्षा करते हुए कहा कि कुछ नगरीय निकाय द्वारा योजना की राशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र नहीं भिजवायें गये उन्हें शीघ्र भिजवायें। उन्होनें शहरी गरीबों से संबंधित इस योजना को मिशन बोर्ड में क्रियान्वित करने के निर्देश दिये एवं कहा कि योजना के तहत सभी संभागीय मुख्यालयों की नगरीय निकायों को 1–1 मॉडल आश्रय स्थल बनाया जाकर संचालित किया जाना है। अतः इस संबंध में विभाग को शीघ्रतिशीघ्र प्रस्ताव भिजवाये जाये।

अमृत योजना के तहत में विभिन्न शहरों में सीवरेज, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज एवं पार्क परियोजना के लिए 312 करोड़ रूपये के कार्यो की स्वीकृती

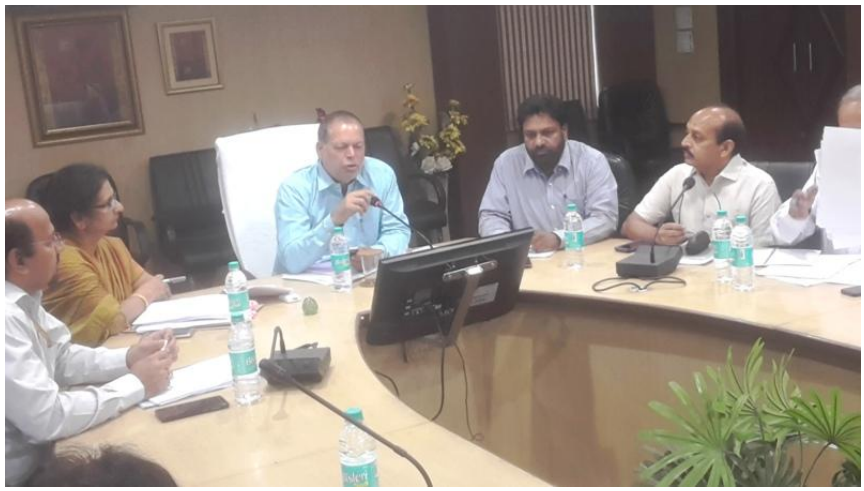

अमृत योजना (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) की स्टेट लेवल टेक्नीकल कमेटी की षष्ठम बैठक में दो सीवरेज परियोजनाओं, चार वाटर सप्लाई परियोजनाओं, एक जल शुद्धिकरण परियोजना एवं पॉच उद्यान परियोजनाओं (डीपीआर) राशि 312 करोड़ रूपये की (कुल 12 परियोजनाओं) की स्वीकृती प्रदान की गई।

बैठक में जयपुर के ताल कटौरा के जल शुद्धिकरण के 5.2 करोड़ रूपये की परियोजना को मंजूरी दी गई।

बैठक में राशि रूपये 312 करोड़ के 12 परियोजनाओं की डीपीआर को स्वीकृती प्रदान की गई। जिसमें दो सीवरेज परियोजनाओं, चार वाटर सप्लाई परियोजनाओं, एक जल शुद्धिकरण परियोजना एवं पॉच उद्यान परियोजनाओं (डीपीआर) राशि 312 करोड़ रूपये की (कुल 12 परियोजनाओं) को स्वीकृती प्रदान की गई। बैठक मे वाटर सप्लाई की चार परियोजना चुरू में 21 करोड़ रूपये, चित्तौड़गढ़ 55 करोड़ रूपये, बीकानेर 35 करोड़ रूपये, हिण्डौन 20.57 करोड़ रूपये की स्वीकृत की गई। इसी प्रकार जयपुर शहर चार दीवारी के भीतर सीवरेज की 49 करोड़ रूपये की एक परियोजना एवं ताल कटौरा जल शुद्धिकरण के 5.2 करोड़ रूपये की एक परियोजना, बीकानेर में 115 करोड़ रूपये की सीवरेज परियोजना को स्वीकृती प्रदान की गई। पॉच उद्यान परियोजनाओं (डीपीआर) में कोटा 2.50 करोड़, श्रीगंगानगर 2.50 करोड़ रूपये, हनुमानगढ़ 2.50 करोड़ रूपये, चित्तौड़गढ़ 2.50 करोड़ रूपये एवं उदयपुर 2.50 करोड़ रूपये की स्वीकृती प्रदान की गई। प्रदेश के 29 अमृत शहरों में GIS Based मास्टर प्लान तैयार करने के लिए 12.16 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई है।

स्वच्छ सर्वेक्षण–2017 देश में 4 जनवरी, 2017 से प्रारम्भ

स्वच्छता सर्वेक्षण–2017 की जानकारी देने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश के 500 शहरों (1 लाख और उससे अधिक आबादी वाले) में स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान प्रारम्भ होगा। स्वच्छता सर्वेक्षण–2017 की जानकारी देने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में 26 अक्टूबर, 2016 को सम्पन्न हुई।

प्रदेश के पहले खुले में शौच मुक्त डूंगरपुर शहर के निकाय प्रमुख श्री के.के. गुप्ता को कार्यशाला में सम्मानित कर प्रशस्ति पत्र दिया गया। इस दौरान पंचायती राज संस्थान सफाई व्यवस्था से जुड़े विभिन्न उपकरणों/वाहनों/साधनों की प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया।

कार्यशाला के प्रारम्भ में प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग डॉ मनजीत सिंह ने बताया कि जनवरी 2016 में देश के 73 शहरों में स्वच्छता रेटिंग के लिए केन्द्रिय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण–2016 का आयोजन किया था। इसी क्रम में 4 जनवरी, 2017 को देश के 500 शहरों में स्वच्छता रेटिंग के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण–2017 का आयोजन किया जा रहा है। उन्होनें बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण–2017 के बारे में निकाय प्रमुखों एवं अधिकारियों को जानकारी देने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उन्होनें बताया कि सर्वेक्षण–2017 का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले आम नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए स्वच्छता मे उनकी भागीदारी एवं जिम्मेदारी सुनिश्चित करना है साथ ही इस सर्वेक्षण से नगरीय क्षेत्रों में नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने मे सुधार करना एवं सभी नगरीय निकायों में एक स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा को जागृत करना है।

स्वच्छ भारत मिशन के राष्ट्रीय मिशन निदेशक एवं संयुक्त सचिव श्री प्रवीण प्रकाश ने स्वच्छ सर्वेक्षण–2017 के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि देश में 4 जनवरी, 2017 से स्वच्छ सर्वेक्षण–2017 प्रारम्भ होगा। उन्होनें बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण–2016 में प्रदेश के तीन शहरों जयपुर की 29वीं रेंकिंग, जोधपुर की 57वीं रेंकिंग एवं कोटा की 58वीं रेंकिंग आयी थी। उन्होनें कहा कि कोई भी शहर तब तक स्मार्ट सिटी नहीं बन सकता जब तक कि वहॉ की सफाई व्यवस्था सुदृढ़ न हो। उन्होनें बताया कि सर्वेक्षण का कार्य Quality Council of India (QCI) के माध्यम से किया जायेगा। इस दौरान सर्वेक्षण में शामिल शहरों में Quality Council of India (QCI) की टीम दो दिवस तक विभिन्न स्थानों का आकस्मिक निरीक्षण करेगी तथा वहॉ की महापौर एवं आयुक्त से भी मिलेगी। उन्होनें सर्वेक्षण के महत्वपूर्ण घटकों की जानकारी देते हुए बताया कि इस सर्वेक्षण का महत्वपूर्ण घटक नागरिकों की भागीदारी है। सोशियल मीडिया व अन्य परम्परागत मिडिया चैनलो का भी राष्ट्रीय, राज्य और शहर स्तर पर प्रयोग किया जायेगा। जिसमें जनता को सर्वेक्षण और सर्वेक्षण विधि के बारे में जानकारी दिये जाने के साथ–साथ सर्वेक्षण में उनकी भागीदारी तथा सभी नागरिकों की भागीदारी सुशिचित की जायेगी। सर्वेक्षण में सोशियल मिडिया, दूरभाष, पत्र एवं आपसी बातचीत के माध्यम से आम जनता से संबंधित शहर की सफाई व्यवस्था के संबंध में Quality Council of India (QCI) टीम फीडबैक लेगी। इस दौरान यह देखा

जाएगा कि संबंधित नगरीय निकाय द्वारा सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वार्ड में बायोमैट्रिक मशीने लगायी गयी है या नहीं। नगरीय निकाय के पास पर्याप्त संख्या में सफाई कर्मचारी नियुक्त है या नही। शहर से उत्पादित होने वाले कचरे के उठाने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध है या नहीं साथ ही वाहनों में वाहन ट्रैकिंग सिस्टम GPS लगा है या नहीं। यदि पर्याप्त साधन उपलब्ध है तो जितना कचरा उत्पादित होता है वह पूरा उठता है या नहीं। ठोर–टू–डोर कचरा संग्रहण की सफलता के लिए रेक पिकर्स को चिन्हित कर उन्हें निकाय द्वारा अपने साथ लिया गया है या नहीं। निकाय क्षेत्र में स्थित वाणिज्यिक क्षेत्रों में कचरा पात्र रखें है या नहीं एवं वहां पर दिन में दो बार सफाई होती है या नहीं। स्थानीय निकाय द्वारा डोर–टू–डोर कचरा संग्रहण के लिए यूजर चार्जेज का कलेक्शन किया जा रहा है या नही। स्थानीय निकाय द्वारा रविवार एवं अन्य राजकीय अवकाश के दिन सफाई व्यवस्था का कार्य किया जा रहा है या नहीं। नगरीय निकाय क्षेत्र में Construction and demolition waste (CDW) को एकत्रित करने की व्यवस्था है या नहीं। निकाय क्षेत्र में रहने वाले आमजन को सर्वेक्षण–2017 के बारे में जानकारी है

या नहीं साथ ही आमजन को स्वच्छता ऐप के बारे में जानकारी है या नहीं। खुले मे शौच मुक्त नगर बनाने के लिए क्या कार्य निती अपनाई जा रहीं है। उन्होने कार्यशाला में सर्वेक्षण की विधि, सर्वेक्षण प्रक्रिया, परिणाम संकेतकों के बारे में जानकारी दी तथा नगरीय निकाय प्रमुखों एवं अधिकारियों द्वारा उठाये गये प्रश्नों का भी जवाब दिया।

स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव श्री पुरूषोत्तम बियाणी ने इस अवसर पर कहा कि 2 अक्टूबर, 2014 को देश में स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ हुआ था प्रदेश में मिशन के तहत घरेलू शौचालयों, सामुदायिक शौचालयों एवं सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के साथ–साथ विभिन्न शहरों को खुले में शौच मुक्त किये जाने का कार्य तेजी से जारी है। इसके अतिरिक्त कचरे के प्रोसेसिंग करने एवं डोर–टू–डोर कचरा संग्रहण करने के लिए एग्रीमेंट किये गये है।

केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय के तकनीकी सलाहकार डॉ रमाकान्त ने कार्यशाला में बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत डीजीएस एण्ड डी रेट कांट्रेक्ट के तहत कचरा परिवहन के वाहनों, डम्पर प्लेसर, रोड स्वीपर, डस्टबीन, हैण्डकार्ट, जेसीबी आदि की ऑनलाईन खरीद नगरीय निकाय द्वारा ऑनलाईन भुगतान के माध्यम से की जा सकती है। इस दौरान स्वायत्त शासन विभाग के मुख्य अभियन्ता श्री के.के. शर्मा ने बताया कि स्वायत्त शासन विभाग द्वारा भी डीजीएस एण्ड डी रेट कांट्रेक्ट के तहत प्रदेश की सभी नगरीय निकायों को ऑटा हूपर, ऑटो टीपर, सीवर जेटिंग मशीन, जेसीबी, डम्पर, प्लेसर एवं डस्टबीन खरीद की सुविधा उपलब्ध करवाई है।

कार्यशाला में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की विषय विशेषज्ञ अल्मित्रा पटेल एवं रागिनी जैन ने विस्तार से जानकारी दी। बीएसएनएल के प्रतिनिधि श्री सुरेश पंचाल ने वाहन जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम की तथा एनबीसीसी इण्डिया के प्रतिनिधि श्री आर.के. धवन ने Construction and demolition waste (CDW) की विस्तार से जानकारी दी। प्रदेश के पहले खुले में शौच मुक्त शहर डूंगरपुर के निकाय प्रमुख श्री के.के. गुप्ता

ने डूंगरपुर को खुले में शौच मुक्त किये जाने के दौरान किये गये कार्या की विस्तार से जानकारी दी। नेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की पूजा लहरी ने स्वच्छता ऐप की जानकारी चलचित्र के माध्यम से दी। कार्यशाला के दौरान स्वच्छ भारत मिशन के विभिन्न घटकों पर बनाये गये 10 चलचित्रों को भी प्रदर्शन किया गया।

अमृत योजना की स्टेट लेवल हाई पावर कमेटी की बैठक में 1232.14 करोड़ रूपये की विभिन्न कार्य योजनाओं प्रस्तावों की अभिशंषा की गई

अमृत योजना (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) की स्टेट लेवल हाई पावर कमेटी की बैठक प्रदेश के मुख्य सचिव श्री ओ.पी. मीणा की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित हुई।

बैठक में 1232.14 करोड़ रूपये की वाटर सप्लाई, सीवरेज, ड्रेनेज, ग्रीन स्पेस की परियोजनाओं के प्रस्तावों को केन्द्र सरकार को स्वीकृती हेतु भेजे जाने की अभिशंषा की गई। मार्च 2017 तक प्रदेश की दो स्थानीय निकाय जिनकी क्रेडिट रेटिंग सर्वोत्तम पायी जायेगी उनके बॉण्ड जारी किये जायेंगे।

बैठक में अमृत योजना (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) के तहत अब तक किये गये कार्यो एवं पूर्व बैठकों में लिये गये निर्णयों की विस्तार से समीक्षा की गई। इस दौरान रूडसिकों के मुख्य अभियन्ता श्री एस.के. गोयल द्वारा अमृत योजना (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) के विभिन्न घटकों पर प्रस्तुतीकरण दिया गया। बैठक में अमृत योजना के स्टेट एनुअल एक्शन प्लान में 1232.14 करोड़ रूपये कि विभिन्न परियोजनाओं को स्वीकृती प्रदान की गई जिनमें वाटर सप्लाई के लिए 411.31 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये इसके अन्तर्गत हिण्डौन सिटी में 20.57 करोड़ रूपये, बीकानेर में 34.95 करोड़ रूपये, जोधपुर में 25 करोड़ में, भरतपुर में 50 करोड़ रूपये, सवाईमाधोपुर में 50 करोड़ रूपये, चुरू में 20.89 करोड़ रूपये, चित्तोड़गड़ में 15 करोड़ रूपये, जयपुर में 50 करोड़ रूपये, कोटा में 10 करोड़ रूपये, अजमेर में 30 करोड़ रूपये, उदयपुर में 30 करोड़ रूपये, झालावाड़ में 75 करोड़ रूपये की परियोजनाएं स्वीकृत की गई। इसी प्रकार सीवरेज परियोजना में 766.50 करोड़ रूपये स्वीकृत की गई। जिसमें बीकानेर की 113.58 करोड़ रूपये, धौलपुर के लिए 24 करोड़ रूपये, सवाई माधोपुर के लिए 24 करोड़ रूपये, बून्दी 47. 71 करोड़ रूपये, भीलवाड़ा 10 करोड़ रूपये, श्रीगंगानगर 10 करोड़ रूपये, पाली 10 करोड़ रूपये, टोंक 10 करोड़ रूपये, किश्नगढ़ 100.29 करोड़ रूपये, जयपुर 171.52 करोड़ रूपये, कोटा 102.19 करोड़ रूपये, अजमेर 68.21 करोड़ रूपये, उदयपुर 75 करोड़ रूपये की विभिन्न परियोजना राशि स्वीकृत की गई।

बैठक में अमृत परियोजना (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) के तहत ड्रेनेज के लिए 18.33 करोड़ रूपये के कार्यो को स्वीकृत किया गया जिसमें चुरू के लिए 6.33 करोड़ रूपये, बारां के लिए 1 करोड़ रूपये, झुझुनू के लिए 1 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई। ग्रीन विकास (उद्यान विकास) के लिए 36 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई जिसमें भिवाड़ी 1.50 करोड़ रूपये, ब्यावर 1.50 करोड़ रूपये, हनुमानगढ़ 1.50 करोड़ रूपये, गंगापुर सिटी 1.50 करोड़ रूपये, हिण्डोन सिटी 1.50 करोड़ रूपये, सुजानगढ़ 1.50 करोड़ रूपये, बीकानेर 1.50 करोड़ रूपये, जोधपुर 1.50 करोड़ रूपये, अलवर 1.50 करोड़ रूपये, भरतपुर 1.50 करोड़ रूपये, सीकर 1.50 करोड़ रूपये, धौलपुर 1.50 करोड़ रूपये, चुरू 1.50 करोड़ रूपये, बारां 1.50 करोड़ रूपये, चित्तोड़गढ़ 1.50 करोड़ रूपये, नागौर 1.50 करोड़ रूपये, बून्दी 1.50 करोड़ रूपये, भीलवाड़ा 1.50 करोड़ रूपये, श्रीगंगानगर 1.50 करोड़ रूपये, पाली 1.50 करोड़ रूपये, झुझुनूं 1.50 करोड़ रूपये, किशनगढ़ 1.50 करोड़ रूपये, जयपुर 1.50 करोड़ रूपये, कोटा 1.50 करोड़ रूपये, अजमेर 1.50 करोड़ रूपये, झालावाड़ 2 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई है।

बैठक में प्रमुख शासन सचिव डॉ मनजीत सिंह ने बताया कि प्रदेश के 29 अमृत शहरों की क्रेडिट–रेटिंग का कार्य तीन ऐजेन्सियों इण्डिया रेटिंग, केयर, क्राईसिल से करवाया जा रहा है। यह कार्य 31 दिसम्बर, 2016 तक पूर्ण हो जाएगा। इसके पश्चात् मार्च 2017 तक प्रदेश की दो स्थानीय निकाय जिनकी क्रेडिट रेटिंग सर्वोत्तम पायी जायेगी उनके बॉण्ड जारी किये जायेंगे। उन्होनें बताया कि प्रदेश के सभी 29 अमृत शहरों में GIS बेस्ड मेपिंग व प्रोपर्टी रिकॉर्ड का डिजिटाईजेशन का कार्य अमृत योजना के तहत करवाया जा रहा है। इस योजना में केन्द्र सरकार द्वारा 12.16 करोड़ रूपये दिये जायेंगे। राजस्थान देश का पहला प्रदेश है जहॉ पर बेस मेपिंग व प्रोपर्टी रिकॉर्ड का डिजिटाईजेशन किया जा रहा है।

स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत प्रदेश के चार शहरों में किये जा रहे कार्यो की समीक्षात्मक बैठक

स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत प्रदेश के चार शहरों जयपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा में किये जा रहे कार्यो की प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग डॉ मनजीत सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को दोपहर 3 बजे सचिवालय में समीक्षा की गई।

बैठक में डॉ मनजीत सिंह ने स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत किये जा रहे एवं किये जाने वाले विभिन्न कार्यो की समीक्षा की एवं इस दौरान स्पेशल परपज व्हीकल (SPV) में कार्य करने वाले कर्मचारी एवं अधिकारी की जानकारी ली गई एवं खाली पदो को तुरन्त भरने के निर्देश दिये। उन्होने बैठक में जयपुर व उदयपुर के प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट कन्सलटेन्ट (PMC) के सन्दर्भ में जानकारी ली। बैठक में कोटा व अजमेर के प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट कन्सलटेन्ट (PMC) के संबंध में बताया गया कि इसके लिये 30 नवम्बर को निविदायें खोली जायेगी।

प्रमुख शासन सचिव ने जयपुर व उदयपुर के स्मार्ट सिटी सलाहकारों को निर्देशित किया कि वे परियोजना के तहत विभिन्न परियोजनाओ में डीपीआर बनाने, निविदा आमन्त्रित करने, कार्यादेश जारी करने, कार्य की पूर्णता की समय सीमा निर्धारित करने आदि की सम्पूर्ण प्रक्रिया को निर्धारित समय में पूरा करने की प्रक्रिया को क्रियान्वित करे। बैठक में रील के चेयरमैन श्री ए.के. जैन ने बताया कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत जयपुर के लिये 50 मेगावॉट, उदयपुर के लिये 15 मेगावॉट, के मास्टर प्लान लगभग बन चुके है। इसी प्रकार अजमेर के लिये 6 मेगावॉट तथा कोटा के लिये 4 मेगावॉट के मास्टर प्लान तैयार किये जा रहे है। कोटा में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत दशहरा मैदान के विकास का कार्य एवं अजमेर में मल्टीलेविल कार पार्किंग के निर्माण के लिये आवश्यक प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है।

डॉ मनजीत सिंह ने बैठक में चारों स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को निर्देशित किया की वे स्मार्ट सिटी परियोजनाओ की निविदा कार्यो में तेजी लाये। उन्होने कहा कि माह दिसम्बर तक जयपुर में 1000 करोड़ रूपये, उदयपुर में 800 करोड़ रूपये, अजमेर में 500 करोड़ रूपये व कोटा में 500 करोड़ रूपये की निविदायें आमन्त्रित किया जाना सुनिश्चित करे।

बैठक में शुद्ध पेयजल, सीवरेज, सोलर, आई.टी, विद्युत वितरण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओ में विभिन्न विभागो द्वारा किये जा रहे कार्यो की विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान उपस्थित अधिकारियों को परियोजना क्षेत्र में कार्यो को गति प्रदान करने के निर्देश भी दिये गये।

प्रमुख शासन सचिव ने निर्देश दिये कि स्मार्ट सिटी के पेनसिटी क्षेत्र में मॉडल रोड़, बैंगलोर की टेन्डर श्योर तकनीक पर निर्मित की जाये। उन्होनें जयपुर की चारदीवारी के भीतर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत रोड़

बनाने तथा नगर निगम एवं सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास रूम स्थापित करने के निर्देश दिये। उन्होने यह निर्देश भी दिये कीं डी.ओ.आई.टी. के साथ समन्वयक स्थापित कर स्मार्ट सिटी परियोजना क्षेत्र में डिजीटल आधारित कार्यो को एकीकृत करना सुनिश्चित करे। जिससे परियोजना में कार्य करने वाले विभिन्न विभाग एक मंच पर आकर प्राप्त ऑकडो का उपयोग अपने कार्य में कर सके। बैठक स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत पब्लिक ट्रासपोर्ट सिस्टम, सार्वजनिक विद्युत व्यवस्था के तारो, सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था के तारो व टेलीफोन के तारो को भूमिगत किये जाने, ठोस कचरा प्रबन्धन, सूचना कियोस्क निर्माण, बस शेलटर निर्माण, पार्किग व्यवस्था, सूचना स्क्रीन लगाने, वाई–फाई एवं एलईडी लाईटे लगाने पर विस्तार से चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिये गये।

———————————————————————————————————————

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2016 के तहत स्थानीय निकाय विभाग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार समाप्त करने की ली शपथ

निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग में शुक्रवार को प्रातः 11 बजे सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2016 के तहत निदेशक एवं संयुक्त सचिव श्री पवन अरोडा के नेतृत्व में सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने की शपथ ली।

भ्रष्टाचार को समाप्त करने में आमजन की सहभागीता सुनिश्चित करने के लिये सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2016 प्रदेश की सभी नगरीय निकायो में 31 अक्टूबर से 5 नवम्बर तक मनाया जा रहा है।

राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक में 36 प्रकरणों को स्वीकृती

राज्य के विभिन्न नगर पालिकाओं एवं परिषदों से संबंधित राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक सोमवार को स्वायत्त शासन भवन के कांफ्रेस हॉल में प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग डॉ. मनजीत सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

बैठक में नगरीय निकाय क्षेत्रों के 93 भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों में से 36 प्रकरणों को स्वीकृती प्रदान की गई।

बैठक में नगरीय निकाय क्षेत्रों के 93 भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों में से 36 प्रकरणों को स्वीकृती प्रदान की गई तथा 16 प्रकरणों को आगामी बैठक में एवं 41 प्रकरणों को निकाय स्तर से आधारभूत सुविधाऐं उपलब्ध कराये जाने में कठिनाई, क्षेत्रफल कम होनें एवं मास्टर प्लान में पार्क खुले स्थल, जन उपयोगी आदि सुविधाऐं आदि होने के कारणों से निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

भू–उपयोग परिवर्तन के जिन 93 प्रकरणों पर समिति द्वारा निर्णय लिया गया वे प्रकरण मुख्य रूप से बीकानेर, उदयपुर, कोटा ब्यावर, मकराना, भीलवाड़ा, किशनगढ़, बाड़मेर, डूँगरपुर, राजसमन्द, हनुमानगढ़, टोक, सिरोही, गंगापुर (भीलवाड़ा), पुष्कर, कुचामन सिटी, आसीन्द, निवाई, उनियारा, बिजयनगर, बयाना, पीलीबंगा, राजलदेसर, पदमपुर, सरदारशहर, चाकसू, सांभरलेक, फुलेरा, नीमकाथाना, शाहपुरा, खेतड़ी, नवलगढ़, सूरजगढ़, चिड़ावा, रींगस, खुडाला–फालना, सादड़ी, पिण्डवाड़ा, फलौदी, शिवगंज, सुमेरपुर, भीनमाल, आमेट, बड़ी सादड़ी, छोटी सादडी, देवगढ़ निम्बाहेड़ा, सलूम्बर, रामगंजमण्डी, तिजारा, कापरेन, फतहनगर सनवाड़ आदि शहरों के प्रकरण थे।

समिति द्वारा परिधि नियंत्रण क्षेत्र में समस्त सुविधायुक्त आवासीय योजनाऐं विकसित किये जाने की सुनिश्चितता हेतु 2 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल की भूमि का ही आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने का निर्णय लिया गया। डा. मनजीत सिंह द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त नगरीय निकायों के अधिकारियों को मुख्यमन्त्री जल स्वावलम्बन योजना (शहरी) के क्रियान्वयन में गति लाने हेतु डीपीआर तैयार किये जाने एवं स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये।

गन्दी बस्ती क्षेत्रों एवं सार्वजनिक स्थानों के पास बने हुए सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय के क्षेत्र में 16 नवम्बर से 30 नवम्बर, 2016 तक विशेष सफाई अभियान

स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत दिनांक 16 नवम्बर से 30 नवम्बर, 2016 तक गन्दी बस्ती क्षेत्रों एवं सार्वजनिक स्थानों के पास बने हुए सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों के क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान चलाने बाबत् दिनांक 11 नवम्बर, 2016 को मिशन निदेशक द्वारा ली गई विडियो कांफ्रेसिंग के दौरान निर्देश दिये गये।

समस्त नगरीय निकाय क्षेत्र में 16 से 30 नवम्बर, 2016 की अवधि में गन्दी बस्ती क्षेत्रों एवं सार्वजनिक स्थानों के पास बने हुए सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों के क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान चलाया जाये।

इस अभियान के दौरान किये जा रहे कार्यो को स्थानीय मिडिया द्वारा कवर किया जाये एवं टीवी समाचारों एवं होर्डिंग्स के माध्यम से अभियान का पूरा प्रचार किया जाये। शहर के प्रमुख स्थानों पर बड़े होर्डिंग्स लगाये जाये।

इस अभियान के दौरान जो सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय पूर्णतयः निर्मित हो चुके है, उनका उद्घाटन एवं जिन सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय का कार्य आरम्भ किया जा रहा है। उनका शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किये जाये।

सभी सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों का प्रतिदिन निकाय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाये। सभी सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय की दीवारों पर पेन्टिंग एवं चित्रकारी की जाये।

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी) के प्रभावी क्रियान्वन हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी) के प्रभावी क्रियान्वन के लिए **"सामाजिक सहभागिता"** विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन स्वायत्त शासन भवन के कांफ्रेस हॉल में शुक्रवार को प्रातः 10:00 बजे निदेशक एवं संयुक्त सचिव श्री पवन अरोड़ा की अध्यक्षता में किया गया।

कार्यशाला के प्रारम्भ में निदेशक एवं संयुक्त सचिव श्री पवन अरोड़ा ने बताया कि मुख्यमंत्री जलस्वावलम्बन योजना का मुख्य उद्देश्य पुराने परम्परागत जलस्त्रोतों जैसे बावड़ी, बड़े तालाब आदि को पुनः चालू करना, मरम्मत करना, जलग्राही बनाना है जिससे इनमें वर्षा के जल का अधिक से अधिक संग्रहण किया जा सके तथा भूमिगत जल स्तर को बढ़ाया जा सके एवं इससे घरेलू एवं पेयजल की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। नगरीय निकाय क्षेत्रों में आवश्यक जल हेतु इस प्रकार से पानी के स्त्रोत तैयार हो सकेंगे। उन्होनें कहा कि जलस्त्रोतों की पुनरूद्धार से सांस्कृतिक एवं धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा भी मिलेगा तथा पर्यावरण एवं शहरी क्षेत्रों में वन विभाग के माध्यम से पौधा रोपण से हरित क्षेत्र बढ़ेगा। जिससे पर्यावरण में व्यापक सुधार हो सकेगा। उन्होनें कहा कि मुख्यमंत्री जलस्वावलम्बन योजना पर 10 दिसम्बर, 2016 से कार्य प्रारम्भ होगा।

निदेशक श्री पवन अरोड़ा ने बताया कि मुख्यमंत्री जलस्वावलम्बन अभियान के तहत प्रदेश के सार्वजनिक भवनों की छतों पर रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के माध्यम से वर्षा जल का संरक्षण भी किया जायेगा। इसके साथ ही 300वर्गगज से अधिक के निजी भवनों में भी वर्षा जल संरक्षण के लिए रूफटॉप रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया जाना सुनिश्चित किया गया है। उन्होनें बताया कि प्रदेश की सभी नगरीय निकायों में तीन वर्ष में जल स्वावलम्बन अभियान के तहत कार्य पूर्ण किये जायेंगे। योजना के प्रथम चरण में प्रत्येक जिले की दो नगरीय निकाय कुल 66 नगरीय निकयों को वर्ष 2016–17 के लिए चयनित किया गया है। योजना के तहत परम्परागत जल स्त्रोतो को जीर्णोद्धार एवं मरम्मत कर भूमिगत जल संचय किया जायेगा। उन्होनें कहा कि योजना के तहत प्रदेश के विभिन्न शहरों द्वारा डीपीआर बनाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है।

श्री अरोड़ा ने कार्यशाला में गैर सरकार संगठनों के प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अतिरिक्त स्वायत्त शासन विभाग की विभिन्न योजनाओं अमृत, एनयूएलएम, एल,ई.डी. स्वच्छ भारत मिशन, डोर–टू–डोर कचरा, शहरों को खुले में शौच मुक्त बनाना, संग्रहण, वेंडिग जोन/नॉन वेंडिग जोन, स्मार्टराज आदि योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी एवं योजनाओं में सहयोग के लिए अपील की। उन्होनें बताया कि स्वायत्त शासन विभाग द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि 500वर्गगज से बड़े भूखण्डों पर भवन निर्माण दौरान यदि वहां पर 10 या 10 से अधिक मजदूर कार्यरत है तो एक अस्थाई शौचालय

बनाना होगा। यदि शौचालय का निर्माण नहीं किया गया तो भवन निर्माण स्वीकृती निरस्त कर दी जायेगी। इसी प्रकार यदि भवन निर्माता द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर बिल्डिंग मैटेरियल/मलबा डाला जाता है तो उसकी भवन निर्माण स्वीकृत निरस्त की जा सकती है।

कार्यशाला में भूजल विभाग के श्री जी.पी. शर्मा ने बताया कि प्रदेश में भूजल भरण 10828.97एमसीएच है तथा जल का दोहन 14843एमसीएच है। उन्होनें बताया कि वर्ष 1984 में प्रदेश के 12 ब्लॉक अत्यधिक जल दोहन के कारण डार्क जोन थे। जबकि वर्ष 2016 में प्रदेश के 112 ब्लॉक डार्क जोन में है। उन्होनें कहा कि रेनवाटर हार्वेस्टिंग एवं रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग से ही भूजल का स्तर बढ़ाया जा सकता है। जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियन्ता श्री दीपक दोषी ने कहा कि आमजन के मध्य पानी को बचाने की जागरूकता आयी है। परन्तु बढ़ती जनसंख्या के कारण पानी की मांग बढ़ी है एवं भूजल स्तर पर गिरावट आयी है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में वर्षा का स्तर पर न्यूनतम रहता है। ऐसे में रेनवाटर हार्वेस्टिंग एवं रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के माध्यम से ही भूजल स्तर बढ़ाया जा सकता है। उन्होनें बताया कि जयपुर में 72 सरकारी भवनों पर रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तैयार किये गये है।

बैठक में मुख्य अभियन्ता श्री के.के.शर्मा ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत घरेलू शौचालयों, डोर–टू–डोर कचरा संग्रहण, कचरे की प्रोसेसिंग के लिए प्लान्ट लगाना एवं खुले में शौच मुक्त शहर बनाने जैसी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी।

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

Local Self Government

Shri Rajpal Singh Shekhawat(Honorable Minister UDH)
(O)Ph No.+91141-2227533,

Shri Manjeet Singh(IAS) - Principal Secretary
Ph No. +91141-2227128

Shri Purushottam Biyani (IAS) Director and Joint Principal Secretary
Ph No.+91141-2222403
Fax: 0141-2222403

Call Center Toll free No.:- 1800-180-6127

Office-Local Self Government Department (Directorate of Local Bodies, Rajasthan, Jaipur) G-3, Rajmahal Residency, Near Civil lines, Railway Crossing, Jaipur - Rajasthan -India

Contact Us